

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7592/2022

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर।
2. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिला अलवर (राज.)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. के.के. गुप्ता (केवल कृष्ण गुप्ता) पुत्र स्वर्गीय श्री हरि प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी कलाली का कुआं, दिल्ली दरवाजा बाहर, अलवर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. डॉ. अभिनव शर्मा, कार्मिक अधिकारी (ओ एंड एम) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिला अलवर (राज.)।

-----उत्तरदाता

संबद्ध

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4189/2022

सचिव प्रशासन आरआरवीएनएल, विद्युत भवन, राजस्थान, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. कुंज बिहारी शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष,

निवासी ग्राम पंसारियन की झोपड़ियां, पोस्ट पंडितपुरा, तहसील बासवा, जिला दौसा।

2. राजस्थान राज्य, उसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. पिंदू कुमार मीणा, वर्तमान में प्रतिवादी के स्थान पर एईएन, 132 केवी, जीएसएस दीगरियाभीम, दौसा के कार्यालय में कार्यरत।

-----उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10660/2022

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, मकरवाली रोड, अजमेर (राजस्थान) अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, मकरवाली रोड, अजमेर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र श्री कपूरा राम, निवासी ग्राम और पोस्ट अंथला, तहसील अबूरोड, सिरोही। वर्तमान में सहायक अभियंता (परियोजना), उदयपुर के कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत।
2. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर।

-----उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10661/2022

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, मकरवाली रोड, अजमेर (राजस्थान) अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

2. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन,
पंचशील नगर, मकरवाली रोड, अजमेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. गौरव सुथार पुत्र श्री ख्याल लाल सुथार, निवासी ग्राम और पोस्ट अंथला,
तहसील अबूरोड, सिरोही, सहायक अभियंता (परियोजना), उदयपुर के पद
पर कार्यरत।
2. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय,
जयपुर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री शैलेश प्रकाश शर्मा
श्री राजेंद्र सोनी
श्री कुणाल रावत
श्री सुरेश कश्यप
श्री हिमांशु थोलिया
श्री राहुल कामवार
श्री अनीश भदाला
श्री अर्जुन शर्मा
श्री संजय मेहला
श्री निखिलेश कटारा
श्री राजेश महर्षि
श्री अभिषेक शर्मा

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता (एडवोकेट
जनरल) के साथ:
श्री दर्श पारीक
सुश्री धृति लड्डा

श्री अशोक बंसल
श्री विनोद कुमार शर्मा
श्री हिमांशु जैन

माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन
आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

आरक्षित दिनांक 29/04/2024

उद्घोषित दिनांक 23/05/2024

प्रस्तावना :

1. वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह में, विवाद का दायरा, हालांकि सीमित नहीं है, लेकिन इसका प्रमुख और व्यापक आधार राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर के क्षेत्राधिकार पर उठाई गई चुनौती है। यह चुनौती जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य निगमों के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने के न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

2. इसलिए, यह देखते हुए कि इन रिट याचिकाओं में कानून के सामान्य प्रश्नों पर निर्णय की आवश्यकता है, सभी पक्षों के वकील की सहमति से, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7592/2022 (शीर्षक: प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम के.के. गुप्ता (केवल कृष्ण गुप्ता) और अन्य) को मुख्य मामले के रूप में लिया जा रहा है। यह सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया जाता है कि इस समूह की रिट याचिकाओं में कोई भी विसंगति केवल उनके तथ्यात्मक विवरणों से संबंधित है, न कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कानूनी प्रश्नों से। इसलिए, यह स्वतः

स्पष्ट है कि इस याचिका का परिणाम/निर्णय, यथावत रूप से, संबंधित याचिकाओं पर भी लागू होगा।

3. यह वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है और इसमें राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद, न्यायाधिकरण) द्वारा अपील संख्या 4219/2021 में 13.04.2022 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में, बिजली कंपनियों/निगमों जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (इसके बाद, जेवीवीएनएल) के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने के न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय दिया गया था, और यह परिणामतः माना गया था कि न्यायाधिकरण जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने के लिए सक्षम होगा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

4. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वाद-विवाद को घेरने वाली व्यापक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

4.1 याचिकाकर्ता- जेवीवीएनएल, जो कि एक विद्युत कंपनी है, ने 20.09.2021 को प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनहित का हवाला देते हुए अपने कर्मचारियों के लिए एक समूह स्थानांतरण आदेश जारी किया।

4.2 इस स्थानांतरण आदेश से व्यथित होकर, स्थानांतरित कर्मचारियों ने 20.09.2021 के इस आदेश के खिलाफ **माननीय न्यायाधिकरण** के समक्ष एक **चुनौती** पेश की।

4.3 परिणामस्वरूप, माननीय न्यायाधिकरण ने 30.09.2021 को एक **अंतरिम आदेश** पारित किया, जिसने 20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश के प्रभाव और संचालन पर **रोक** लगा दी।

4.4 माननीय न्यायाधिकरण द्वारा स्थानांतरित कर्मचारियों के पक्ष में 30.09.2021 को पारित अंतरिम आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल ने पहली बार एक अलग याचिका के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क किया, जिसमें 09.03.2022 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने मामले को **माननीय न्यायाधिकरण** के पास वापस भेज दिया, ताकि जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की वैधता के संबंध में याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल द्वारा उठाई गई आपति पर **निर्णय** किया जा सके। संक्षेप में, माननीय न्यायाधिकरण को अपने ही क्षेत्राधिकार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, जहाँ तक यह जेवीवीएनएल के कर्मचारियों के मामलों से संबंधित था।

4.5 **13.04.2022** के **चुनौतीपूर्ण आदेश** के तहत, माननीय न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल की आपति पर निर्णय दिया और यह माना कि माननीय न्यायाधिकरण **जेवीवीएनएल के कर्मचारियों से संबंधित मामलों** पर निर्णय लेने के लिए

क्षेत्राधिकार में सक्षम है, जिसमें उसके कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ उठाई गई चुनौती भी शामिल है। चुनौतीपूर्ण आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

"14. हमने सभी पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और केस रिकॉर्ड देखा है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विद्युत वितरण निगम इस न्यायाधिकरण में नियमित रूप से कई मामलों में लड़ रहा है। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि हाल के दिनों में आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामले सुलझाए गए हैं, जिसमें विद्युत वितरण निगम एक पक्ष था।

15. हमें यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि अचानक इस मामले में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के संबंध में **आरसीएसएटी** के क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि निगम न केवल नियमित रूप से **आरसीएसएटी** में मामलों में भाग ले रहा है, बल्कि अपने अन्य कर्मचारियों से संबंधित मामलों को लोक अदालतों में भी सुलझा रहा है।

16. माननीय उच्च न्यायालय के 28.1.2008 और 15.5.2009 के आदेशों के मुद्दे के संबंध में, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील से सहमत हैं कि क्षेत्राधिकार का मुद्दा समय के साथ विकसित हो रहा है और यह केवल 2008 में जारी किए गए आदेश पर आधारित नहीं हो सकता है।

17. हमारे सामने उपलब्ध सभी सामग्री, पूर्वोदाहरणों और तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम मानते हैं कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के संबंध में **आरसीएसएटी** का क्षेत्राधिकार है।

18. मामले की सुनवाई के लिए **01.05.2022** को गुण-दोष के आधार पर सूचीबद्ध किया जाए।"

4.6 इस स्तर पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि 13.04.2022 के आदेश के माध्यम से, क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर माननीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था, लेकिन

20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश के खिलाफ दायर अपील के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए, आज की तारीख में, 20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश की शुद्धता और/या वैधता पर निर्णय अभी भी लंबित है, जबकि स्थानांतरित कर्मचारी 30.09.2021 के अंतरिम आदेश के माध्यम से दी गई अंतरिम सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं।

4.7 परिणामस्वरूप, माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 13.04.2022 के चुनौतीपूर्ण आदेश से व्यथित होकर, जिसने याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने के अपने क्षेत्राधिकार को बनाए रखा, बाद वाले ने यह याचिका दायर की है।

4.8 जब मामला इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, तो यह उचित समझा गया कि अन्य याचिकाएं, जिनमें विवाद समान था, जहां अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) और अन्य जैसी अन्य बिजली कंपनियों की ओर से माननीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई थी, को कानून के बिंदु पर व्यापक निर्णय के लिए इस याचिका के साथ टैग किया जाए। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय के समक्ष याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया और आज सामूहिक रूप से निपटान के लिए लिया गया है।

4.9 सुनवाई के दौरान, मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने 03.04.2024 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले

महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर बार के सदस्यों की व्यापक भागीदारी का आह्वान किया।

कॉज-लिस्ट में प्रकाशित नोट इस प्रकार था:

"इस मामले में, याचिकाओं के समूह में, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (आरएटी) के क्षेत्राधिकार को ही चुनौती दी गई है।

इस पृष्ठभूमि में, यह ध्यान दिया जाता है कि याचिकाकर्ता एक सरकारी कंपनी है, जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ प्रदान करती है। इस कंपनी में बहुमत शेयरधारिता, यानी लगभग 100%, सरकार की है।

*उपरोक्त के बावजूद, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि इस याचिकाकर्ता-कंपनी के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरएटी के प्रावधानों में याचिकाकर्ताओं और उनके कर्मचारियों को आरएटी से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने **अनिल पारीक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**, डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 711/2023 के फैसले पर भरोसा किया।"*

बार की व्यापक भागीदारी को भी आमंत्रित किया जाता है।"

4.10 इस पृष्ठभूमि में, विद्वान महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री हिमांशु थोलिया, श्री शैलेश प्रकाश शर्मा, श्री अशोक बंसल, श्री कुणाल रावत और श्री प्रणव भंसाली, ने अन्य लोगों के साथ, संबंधित पक्षों की ओर से अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

5. सबसे पहले, श्री शैलेश प्रकाश शर्मा और श्री हिमांशु जैन ने, 13.04.2022 के चुनौतीपूर्ण आदेश के खिलाफ अपनी शिकायत व्यक्त करते हुए, प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार **कानून द्वारा सृजित** है और यह

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1976 (इसके बाद, 1976 का अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

6. इस पृष्ठभूमि में, विद्वान वकील ने धारा 2(ए), जो 'सिविल सेवा' को परिभाषित करती है; धारा 2(सी), जो 'सरकारी सेवक' को परिभाषित करती है; धारा 2(एफ), जो 'सेवा मामलों' को परिभाषित करती है; और धारा 4, जो 'अपील दायर करने' को परिभाषित करती है, पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का वैधानिक अधिकार तभी प्रयोग किया जा सकता है जब अपीलकर्ता 1976 के अधिनियम के संदर्भित प्रावधानों के अनुसार 'व्यक्ति' व्यक्ति की श्रेणी में आता हो।

7. तदनुसार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 1976 के अधिनियम की धारा 4 माननीय न्यायाधिकरण को किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा किसी भी सेवा मामले या 'सरकारी सेवक' को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में प्रभावित करने वाले मामलों पर पारित आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देती है। 'सरकारी सेवक' शब्द पर जोर देते हुए, यह तर्क दिया गया कि धारा 2(सी) उन व्यक्तियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करती है जिन्हें 'सरकारी सेवक' माना जा सकता है। इसमें शामिल हैं: (i) एक व्यक्ति जो राजस्थान सरकार के तहत एक सिविल सेवा का सदस्य है या रहा है या एक सिविल पद धारण करता है या किया है, जिसमें विदेशी सेवा में ऐसा कोई व्यक्ति या जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के निपटान में रखी गई हैं; (ii) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण की सेवा में कोई भी व्यक्ति जिसकी सेवाएं अस्थायी

रूप से राज्य सरकार के निपटान में रखी गई हैं; (iii) अनुबंध पर सेवा में एक व्यक्ति या एक व्यक्ति जो कहीं और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और राजस्थान सरकार के तहत फिर से नियोजित है।

8. यह कहने के बाद, विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 'सरकारी सेवक' की उपरोक्त परिभाषा से मुख्य निष्कर्ष यह है कि उक्त व्यक्ति राज्य की 'सिविल सेवाओं' का सदस्य होना चाहिए। तदनुसार, धारा 2(ए) 'सिविल सेवाओं' को राजस्थान राज्य की सिविल सेवाओं और ऐसी अन्य सेवाओं के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

9. इसलिए, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल एक निगम होने के नाते, केवल तभी 'सिविल सेवा' माना जाएगा और परिणामस्वरूप इसके कर्मचारियों को 'सरकारी सेवक' माना जाएगा, यदि राज्य द्वारा जेवीवीएनएल की सेवाओं को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। हालांकि, ऐसी राजपत्र अधिसूचना के अभाव में, जेवीवीएनएल के कर्मचारियों को किसी भी तरह से सरकारी सेवक नहीं माना जा सकता है और इसलिए, उनकी शिकायत को माननीय न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी 1976 के अधिनियम के संदर्भित प्रावधानों के अनुसार एक व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा 13.04.2022 के चुनौतीपूर्ण आदेश में अपनाया गया तर्क, जहाँ तक यह पिछली प्रथा के कारण क्षेत्राधिकार को बनाए रखने से संबंधित था, गलत और ऐसे

न्यायाधिकरणों की योजना और/या दायरे को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

10. उपरोक्त के अनुसरण में, यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक सरकारी सेवक को एक निगम के कर्मचारियों के साथ समान नहीं माना जा सकता है, जैसे कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल, जिसका नियंत्रण उसके निदेशक मंडल के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे निगम में 100% शेयरधारिता राज्य सरकार की है। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि एक सरकारी कंपनी की पहचान सरकार से अलग होती है और तदनुसार, इसके कर्मचारियों को 'सिविल सेवक' नहीं माना जा सकता है, जब तक कि राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अन्यथा अधिसूचित न किया जाए।

11. उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, **डी.बी. एसएडब्ल्यू संख्या 711/2023** जिसका शीर्षक *अनिल पारीक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, प्यारे लाल शर्मा बनाम प्रबंध निदेशक (1989) 3 एससीसी 448, ए.के. बिंदल बनाम भारत संघ (2003) 5 एससीसी 163, आई.डी.पी.एल. के अधिकारी और पर्यवेक्षक बनाम अध्यक्ष और एम.डी., आई.डी.पी.एल. (2003) 6 एससीसी 490, रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ एआईआर 1967 एससी 1887, विजय चंद थानवी बनाम प्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और अन्य (2008) 3 आरएलडब्ल्यू 2659 में दिए गए फैसलों पर भरोसा किया गया।*

12. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के लिए पैनल के वकील श्री शैलेश प्रकाश शर्मा ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ट्रांसफर स्कीम 2000, संबंधित राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक्ट 1999 के साथ मिलकर, निगम के बोर्ड/डिस्कॉम की परिभाषा को स्पष्ट करती है, जो अपने कर्मचारियों/कर्मियों पर उनके स्थानांतरण आदि सहित प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण प्रदान करती है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि जब तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल जैसे कई निगमों में भंग कर दिया गया था, तो संबंधित निगमों को तत्कालीन बोर्ड से ऐसे निगमों में स्थानांतरित होने वाले कर्मियों पर सभी प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था। तदनुसार, 2000 की उक्त योजना के खंड 6(5)(ई) में यह प्रावधान था कि विभिन्न निगमों में स्थानांतरित होने वाले कर्मी पूर्व राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की सेवा में नहीं रहेंगे और परिणामस्वरूप, वे राज्य सरकार और/या बोर्ड के तहत सेवा के किसी भी लाभ का दावा या मांग नहीं करेंगे।

13. अंत में, श्री शर्मा ने तर्क दिया कि 2000 की योजना के अनुसार, संबंधित वितरण कंपनियों/निगमों, जैसे कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल, के गठन के बाद, इसके सभी कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थीं या जेवीवीएनएल में जारी रहे थे, वे जेवीवीएनएल/निगम के कर्मचारी बने रहेंगे और ऐसे कर्मचारियों को राज्य सरकार या तत्कालीन राज्य विद्युत बोर्ड के खिलाफ किसी भी अधिकार या हित का दावा करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। तदनुसार, तत्कालीन बोर्ड का एक कर्मचारी याचिकाकर्ता-

जेवीवीएनएल का कर्मचारी बनने के बाद, सभी उद्देश्यों के लिए, जेवीवीएनएल के निदेशक मंडल द्वारा उसके लिए निर्धारित सेवा की शर्तों के साथ उसका कर्मचारी बन गया और उसके बाद, ऐसे कर्मचारी को राज्य सरकार/बोर्ड या किसी अन्य हस्तांतरिती के खिलाफ किसी भी अधिकार या हित का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। परिणामस्वरूप, यह कहा गया कि जेवीवीएनएल **कंपनी अधिनियम, 1956** के प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से निगमित एक कंपनी है। उक्त कंपनी के **ज्ञापन-पत्र** के साथ संलग्न उसके **संघ के अनुच्छेद** में, जेवीवीएनएल के निदेशक मंडल को उसके **अनुच्छेद 29** के अनुसार कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन करना था।

14. इसलिए, यह दावा किया गया कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारी किसी भी तरह से माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत नहीं उठा सकते थे, क्योंकि ऐसे कर्मचारी 1976 के अधिनियम द्वारा निर्धारित **सरकारी सेवक** की श्रेणी में नहीं आते हैं।

बी. उत्पादों की ओर से प्रस्तुतियाँ

15. विद्वान महाधिवक्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद, ने राज्य की ओर से उपस्थित होकर, माननीय न्यायाधिकरण के क्षेत्रीय दायरे को संक्षेप में बताया और प्रस्तुत किया कि अपील केवल **1976 के अधिनियम की धारा 4** के तहत ही दायर की जा सकती है, क्योंकि '**सरकारी सेवक**' शब्द का एक वैधानिक अर्थ है जैसा कि उक्त अधिनियम की **धारा 2(सी)** में परिभाषित है। इसलिए, चूंकि '**सरकारी सेवक**' शब्द एक सिविल सेवा के सदस्य को संदर्भित करता है जो एक सिविल पद धारण करता है या कर चुका है, तो सिविल

सेवाओं की परिभाषा, जो कि एक विस्तृत परिभाषा है, भी न्यायालय के विचार के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

16. आगे यह तर्क दिया गया कि **1976 के अधिनियम** के तहत परिकल्पित **सरकार**, राज्य की कार्यपालिका है, जिसकी सिविल सेवाएं उसके कार्यकारी कार्यों का निर्वहन करने के लिए बनाई गई हैं। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल जैसे निगम, जो कानून द्वारा या निगमन द्वारा कुछ कार्यों का निर्वहन करने के लिए बनाए गए हैं जो सरकार भी कर सकती है, वे केवल उक्त राज्य सरकार के **साधन** हैं, जिससे वे राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं बनते हैं। तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि **भारत के संविधान का भाग-III**, जो 'राज्य' को परिभाषित करता है, को राज्य सरकार के साथ समान नहीं माना जा सकता है, जिनके अलग-अलग अर्थ और संदर्भ हैं, क्योंकि 1976 का विशेष अधिनियम केवल सेवा मामलों और उसके निर्दिष्ट कर्मचारियों से संबंधित है, जबकि संविधान का भाग-III सरकार और उसके साधनों के संबंध में मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसका सामूहिक रूप से अर्थ है कि 'राज्य' अपने व्यापक अर्थों के साथ।

17. अंत में, श्री प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के समक्ष विवाद अब **पुनरावृत्ति** नहीं है, क्योंकि इसी मुद्दे को इस न्यायालय की खंडपीठ ने **अनिल पारीक (उपरोक्त)** में तय किया है, जहां मामला **राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन** के कर्मचारियों के संबंध में 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत माननीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि एक बाध्यकारी पूर्वोदाहरण के रूप में, जिसने राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के संबंध में

न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया था, उसी का वर्तमान मामले में भी पालन किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।

सी. प्रतिवादियों की ओर से

18. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील, श्री कुणाल रावत और श्री अशोक बंसल ने प्रस्तुत किया कि **13.04.2022** का चुनौतीपूर्ण आदेश इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है, क्योंकि यह कानून की स्थापित स्थिति और अभ्यास के अनुरूप पारित किया गया है। इस दावे के समर्थन में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तत्कालीन **राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड** को 18.01.2002 की अधिसूचना द्वारा पाँच कंपनियों में विभाजित किया गया था। ये सभी 5 कंपनियां- जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरआरवीएनएल और आरआरवीयूएनएल **कंपनी अधिनियम** के तहत पंजीकृत हैं। इन निगमों में **राजस्थान राज्य सरकार** की 100% शेयरधारिता है और परिणामस्वरूप, इन बिजली वितरण कंपनियों पर सभी वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण **राजस्थान सरकार** के पास है। याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल जैसी ये कंपनियां केवल बिजली वितरण के विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं, जिसके लिए उनके पास उनके निदेशक मंडल होते हैं, जो उक्त कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करते हैं। हालांकि, यह दावा किया गया कि कर्मचारियों के मामलों पर, सभी निर्णय **राज्य सरकार की** स्वीकृति से लिए जाते हैं, क्योंकि ये कंपनियां राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी कर्मचारी की भर्ती नहीं कर सकती हैं। कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दे, उनके वित्तीय लाभों

सहित, राज्य सरकार की स्वीकृति से भी उठाए जाते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में जारी किए गए सभी परिपत्रों और आदेशों को याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल द्वारा भी अपनाया जाता है। वास्तव में, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कोई भी सेवा नियम **राजस्थान सेवा नियमों** से भिन्न नहीं हैं।

19. इसलिए, यह तर्क दिया गया कि चूंकि राज्य सरकार याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल पर उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण रखती है, 'कंपनी/निगम' का नाम अप्रासंगिक होगा और याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों को सरकारी सेवक माना जाएगा, जो अपनी शिकायतें माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष रख सकते हैं।

20. इसके अलावा, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने यह भी दावा किया कि अनादि काल से, प्रथागत अभ्यास के अनुसार, माननीय न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों की शिकायतों को स्वीकार किया है। बल्कि, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल ने भी अतीत में माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष शिकायतें उठाई हैं। इसके अलावा, आज तक जेवीवीएनएल द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों की स्वीकार्यता के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। इसलिए, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल को अपनी पिछली प्रथा से पलटने और याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को बाहर करने के लिए प्रार्थनाएं करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21. उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, गुजरात राज्य और अन्य बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य (1983) 2 एससीसी 33; असम राज्य बनाम श्री कनक चंद्र दत्ता (1967) 1 एससीआर 679; पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक बनाम पी.के. राजाम्मा (1977) 2 एससीसी 94; मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन (2002) 2 एससीसी 167; और एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7703/2019 जिसका शीर्षक *अवधेश दुबे बनाम सचिव, स्व-शासन विभाग* में दिए गए फैसलों पर भरोसा किया गया।

22. अंत में, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए और परिणामस्वरूप, **13.04.2022** के चुनौतीपूर्ण आदेश को **30.09.2021** को प्रतिवादियों के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश के साथ बनाए रखा जाए। वैकल्पिक रूप से, यह भी प्रार्थना की गई कि या तो **20.09.2021** के स्थानांतरण आदेश, जिसके खिलाफ प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया था, को रद्द और समाप्त कर दिया जाए, या मामले को गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निपटान के लिए माननीय न्यायाधिकरण के पास वापस भेज दिया जाए।

चर्चा और निष्कर्ष

23. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया गया, वर्तमान याचिका के रिकॉर्ड की जांच की गई और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

24. गुण-दोष पर चर्चा से पहले, यह न्यायालय इस न्यायालय के समक्ष विवाद को घेरने वाले निम्नलिखित अपरिहार्य तथ्यों और/या शर्तों पर ध्यान देना आवश्यक समझता है:

24.1 याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल जैसे निगमों के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के निर्धारण और/या सुनिश्चितता के संबंध में वर्तमान विवाद, पहली बार न्यायाधिकरण के समक्ष उठाई गई प्राथमिक शिकायत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, जो 20.09.2021 के समूह स्थानांतरण आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित था।

24.2 याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कुछ कर्मचारियों को स्थानांतरित करने वाला 20.09.2021 का आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनहित का हवाला देते हुए पारित किया गया था।

24.3 30.09.2021 के अंतरिम आदेश के माध्यम से माननीय न्यायाधिकरण द्वारा 20.09.2021 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने के बाद, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल, यानी स्थानांतरण आदेश जारी करने वाली संस्था, ने एक पुरानी याचिका के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 30.09.2021 का आदेश याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों की अपील की गैर-स्वीकार्यता के संबंध

में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति की घोर उपेक्षा में पारित किया गया था। परिणामस्वरूप, यह दावा किया गया था कि 30.09.2021 का आदेश पारित करते समय, न्यायाधिकरण ने जेवीवीएनएल की प्रारंभिक आपत्ति पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था।

24.4 परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल की प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय के लिए विवाद को माननीय न्यायाधिकरण के पास वापस भेजना उचित समझा, जिसमें उसके कर्मचारियों की शिकायतों की न्यायाधिकरण के समक्ष गैर-स्वीकार्यता से संबंधित निर्देश थे।

24.5 परिणामस्वरूप, **13.04.2022** के चुनौतीपूर्ण आदेश के माध्यम से, माननीय न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल द्वारा व्यक्त की गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया और यह माना कि न्यायाधिकरण जेवीवीएनएल के कर्मचारियों से संबंधित मामलों का निर्णय करने के लिए **क्षेत्राधिकार में सक्षम** है, जिसमें उसके कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ उठाई गई चुनौती भी शामिल है।

24.6 परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका के माध्यम से, न्यायाधिकरण को जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने में सक्षम बनाने वाले **13.04.2022** के चुनौतीपूर्ण आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

24.7 इस बीच, 20.09.2021 का स्थानांतरण आदेश, जो इस विवाद का मूल कारण था, न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा के कारण लगभग 3 साल की अवधि के लिए रोक दिया गया है।

25. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय को यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल और उसके व्यथित कर्मचारियों के बीच बाद में हुए मुकदमे के कारण, 20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश से संबंधित प्राथमिक विवाद, जिसने अनजाने में न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के मुद्दे को जन्म दिया, को लगभग तीन साल की अवधि के लिए अनसुलझा छोड़ दिया गया है। 20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश के पारित होने की तारीख से तीन साल की यह चूक विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती है जब यह ध्यान दिया जाता है कि उक्त स्थानांतरण आदेश याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कामकाज के भीतर कुछ प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण पारित किया गया था, जिसे यदि हल नहीं किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर प्रदान की जा रही सेवाओं पर इसका **व्यापक प्रभाव** पड़ सकता है।

26. इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि तीन साल की इस निरंतर अवधि में, जबकि माननीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के उत्पन्न हुए मुद्दे पर कई प्रयास किए गए, दोनों पक्षों के वकील यानी याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल, जिसने स्थानांतरण आदेश जारी किया था, और यहाँ प्रतिवादी, जो उक्त आदेश से प्रभावित पक्ष थे, इस तथ्य को भूल गए कि तीन साल की इस देरी से केवल जनता को ही कठिनाई हो सकती है, यदि उद्धृत प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया, या कम से कम उक्त आवश्यकताओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया।

27. संक्षेप में, 30.09.2021 के अंतरिम आदेश के पारित होने के बाद से, 20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश से संबंधित प्राथमिक मुद्दा पीछे चला गया और

अपनी प्रासंगिकता खो दी, क्योंकि इसे तीन साल की एक लंबी अवधि के लिए रोक दिया गया था और अनजाने में, अंतरिम आदेश की आड़ में, स्थानांतरित कर्मचारी आज तक उनके पक्ष में दी गई रोक का लाभ उठाते रहे, जबकि प्रशासनिक आवश्यकताएं निर्णायक निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थीं।

28. इसलिए, भारत के संविधान के **अनुच्छेद 226** के तहत प्रदान किए गए इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए, यह न्यायालय सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रारंभिक/उत्पन्न हुए मुद्दे पर निर्णय लेना उचित समझता है, यानी 20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश के खिलाफ उठाई गई चुनौती के संबंध में, जिसने एक सामान्य आदेश के माध्यम से, प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनहित का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कई कर्मचारियों को स्थानांतरित किया था।

29. परिणामस्वरूप, आज की तारीख में, यह न्यायालय 20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश को, निम्नलिखित कारणों से और यहाँ नीचे बताए गए अधिकारों के साथ, **रद्द और समाप्त** करना उचित समझता है:

29.1 20.09.2021 का समूह स्थानांतरण आदेश लगभग 3 साल पहले प्रशासनिक आवश्यकताओं और सार्वजनिक उपयोगिता का हवाला देते हुए पारित किया गया था। हालांकि, 30.09.2021 के अंतरिम आदेश के कारण, उक्त स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी गई और परिणामस्वरूप, स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके प्रारंभिक पोस्टिंग स्थान पर अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी गई।

29.2 आज की तारीख में, उक्त आदेश के पारित होने के बाद से लगभग 3 साल बीत चुके हैं। इसलिए, उस समय उत्पन्न हुई प्रशासनिक आवश्यकताएं आज की तारीख में मौजूद हो भी सकती हैं और नहीं भी।

29.3 प्रशासनिक आवश्यकताएं न केवल समय के साथ बल्कि परिस्थितियों के साथ भी बदलती रहती हैं। जो आज एक आवश्यकता हो सकती है, वह कल नहीं हो सकती है और इसके विपरीत, अतीत में उत्पन्न हुई एक आवश्यकता, समय के परिवर्तन के बावजूद, कुछ निश्चित परिस्थितियों के कारण मौजूद रह सकती है।

29.4 इसके अलावा, कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, स्थानांतरण आदेशों में न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा बहुत कम है। **शिल्पी बोस (श्रीमती) और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य** (1991 सप्लीमेंट. (2) एससीसी 659) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया था कि न्यायालय को ऐसे स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो जनहित में और प्रशासनिक कारणों से, वैधानिक नियम के विरुद्ध या दुर्भावना के आधार पर किए गए हों। इसी तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस.के. नौशाद रहमान बनाम भारत संघ और अन्य** (2022) 12 एससीसी 1 में माना कि यह सेवा और प्रशासन की आवश्यकताएं हैं जो इस बात में **सर्वोपरि** होंगी कि एक कर्मचारी को 'कब' और 'कहाँ' तैनात किया जाएगा। परिणामस्वरूप, किसी कर्मचारी की अपनी पसंद की जगह पर तैनाती, विशेष रूप से जब वह एक हस्तांतरणीय नौकरी पर कार्यरत हो, तो यह अनिवार्य रूप से उनका मौलिक अधिकार नहीं बनता है जिसे न्यायालयों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

29.5 इसलिए, यह न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनहित के कारण पारित स्थानांतरण आदेशों में न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा बहुत कम है; कि विचाराधीन स्थानांतरण आदेश सितंबर 2021 में उत्पन्न हुई प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण पारित किया गया था; कि उक्त स्थानांतरण आदेश के पारित होने के बाद से, स्थानांतरित कर्मचारी (यहाँ प्रतिवादी) लगभग 3 साल की अवधि के लिए 30.09.2021 के अंतरिम आदेश के लाभों का लाभ उठा रहे हैं; कि सितंबर 2021 के बाद से काफी समय बीत चुका है और उस समय उत्पन्न हुई प्रशासनिक आवश्यकताओं को आज की तारीख में आवश्यक रूप से और/या निर्णायक रूप से मौजूद नहीं माना जा सकता है, **20.09.2021** के स्थानांतरण आदेश को **रद्द और समाप्त** करना उचित समझता है, इस शर्त के साथ कि आगे चलकर, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल, यदि कोई प्रशासनिक आवश्यकताएं हों, तो उनका विधिवत ध्यान रखने के बाद, इस आदेश के पारित होने की तारीख से **पंद्रह दिन की अवधि** के भीतर प्रतिवादियों के संबंध में आगे के स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

29.6 कार्यवाही के दौरान इस न्यायालय या माननीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल/नियोक्ता को कोई हानि नहीं होगी।

30. इसलिए, ऊपर सूचीबद्ध टिप्पणियों के आलोक में, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल द्वारा जारी किया गया **20.09.2021** का स्थानांतरण आदेश उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ रद्द और समाप्त किया जाता है।

31. 20.09.2021 के स्थानांतरण आदेश से संबंधित मुद्दे को हल करने के बाद, यह न्यायालय अब कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज करना उचित समझता है जिस पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है, अर्थात् याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपीलों की स्वीकार्यता के संबंध में।

32. इसलिए, कानून के उक्त महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्धारण के इस प्रारंभिक चरण में, यह न्यायालय न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुद्दों को रेखांकित करना उचित समझता है, अर्थात्:

(i) क्या किसी भी कंपनी/निगम या किसी वैधानिक निकाय के तहत काम करने वाले कर्मचारी, जो सरकार के स्वामित्व और/या नियंत्रण में हैं, को सिविल पदों पर सेवा देने वालों के बराबर सरकारी सेवक माना जाएगा या नहीं?

(ii) क्या राजस्थान सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के पास किसी भी कंपनी/निगम या किसी वैधानिक निकाय के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से अपील को स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार है, जो राज्य सरकार के स्वामित्व और/या नियंत्रण में हैं?

33. संक्षेप में, माननीय न्यायाधिकरण द्वारा 13.04.2022 के चुनौतीपूर्ण आदेश में अपने क्षेत्राधिकार को बनाए रखने के लिए अपनाया गया तर्क इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि पिछली प्रथा के अनुसार, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल ने समय-समय पर माननीय

न्यायाधिकरण के समक्ष अपने कर्मचारियों के संबंध में कई मामलों में भाग लिया था। इसके अलावा, अतीत में जेवीवीएनएल द्वारा अपने कर्मचारियों की अपीलों की गैर-स्वीकार्यता के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और इसलिए, जेवीवीएनएल अचानक अपनी बात से पलट नहीं सकता था और न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दे सकता था। संक्षेप में, न्यायाधिकरण ने प्रथागत अभ्यास का हवाला देते हुए अपने क्षेत्राधिकार को बनाए रखा।

34. इस स्तर पर, माननीय न्यायाधिकरण की याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों की अध्यक्षता करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए, इस न्यायालय को इस तथ्य पर उचित विचार करना चाहिए कि भारत का संविधान देश के भीतर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए संसद को अधिकार देता है। तदनुसार, राजस्थान राज्य के विधानमंडल ने **1976 का अधिनियम** लागू किया जो सेवा मामलों और उससे संबंधित मामलों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है।

35. इसलिए, यह तथ्य कि न्यायाधिकरण एक कानून की देन है, यानी 1976 का अधिनियम, यह विचार स्थापित करता है कि उक्त न्यायाधिकरण का कामकाज विशुद्ध रूप से उक्त कानून के जनादेश के अनुसार होगा और किसी भी तरह से, न्यायाधिकरण उन मामलों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार को पार नहीं कर सकता है जिन पर वह अध्यक्षता कर सकता है, जैसा कि 1976 के अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है।

36. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय ऊपर निर्धारित कानून के प्रश्न(नों) के प्रभावी निर्णय के लिए 1976 के अधिनियम के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझता है। वे नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं

"2. परिभाषाएँ : इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) **"सिविल सेवाएँ"** का अर्थ राजस्थान राज्य की सिविल सेवाएँ और ऐसी अन्य सेवाएँ हैं जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा:

(i) राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा और राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्य;

(ii) राजस्थान के लिए न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के कर्मचारी;

(iii) राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी; और

(iv) राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारी;

(बी) **"सरकार"** का अर्थ राज्य सरकार है;

(सी) **"सरकारी सेवक"** का अर्थ वह व्यक्ति है जो एक सिविल सेवा का सदस्य है या रहा है या जो राजस्थान सरकार के अधीन एक सिविल पद धारण करता है या कर चुका है और इसमें विदेशी सेवा में ऐसा कोई व्यक्ति या जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के निपटान में रखी गई हैं और किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण की सेवा में कोई भी व्यक्ति जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से राज्य सरकार के निपटान में रखी गई हैं या अनुबंध पर सेवा में एक व्यक्ति या एक व्यक्ति जो कहीं और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और राजस्थान सरकार के तहत फिर से नियोजित है, लेकिन इसमें भारतीय संघ या एक राज्य सरकार की सिविल

सेवा में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होता रहेगा;

(डी) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

(एफ) "सेवा मामला" का अर्थ एक सरकारी सेवक से संबंधित निम्नलिखित मामलों में से एक या एक से अधिक है:

(i) वरिष्ठता;

(ii) पदोन्नति;

(iii) स्थायीकरण ;

(iv) वेतन निर्धारण ;

(v) एक आदेश जो दंड के अलावा किसी सरकारी सेवक के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों को उसके नुकसान के लिए नकारता या बदलता है;

(vi) एक उच्च सेवा, ग्रेड या पद में अस्थायी रूप से कार्य करते समय निम्न सेवा, ग्रेड या पद में वापसी के मामले, जो दंड के अलावा हों;

(vii) पेंशन को रोकना या अधिकतम पेंशन को नकारना, जो दंड के अलावा हो;

(viii) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य मामला।

4. न्यायाधिकरण के कर्तव्य: (1) राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा किसी भी सेवा मामले या किसी सरकारी सेवक को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में प्रभावित करने वाले मामलों पर पारित आदेश के खिलाफ एक अपील सुनेगा।

(2) न्यायाधिकरण को उस आदेश की पुष्टि करने, बदलने या पलटने की शक्ति होगी जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है या उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नए निर्णय के लिए मामले को वापस भेजने की शक्ति होगी।"

[4 ए. अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अन्य उपाय समाप्त न हो गए हों:] (1) न्यायाधिकरण सामान्यतः अपील तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अपीलकर्ता ने

प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया है।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को शिकायतों के निवारण के लिए प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा:

(ए) यदि सरकार या अन्य प्राधिकरण या समिति या अधिकारी या ऐसे नियमों के तहत ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा, शिकायत के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किसी भी अपील या किए गए प्रतिनिधित्व को खारिज करते हुए एक अंतिम आदेश दिया गया है; या

(बी) जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई अपील या किए गए प्रतिनिधित्व के संबंध में सरकार या अन्य प्राधिकरण या समिति या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है, यदि उस तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त हो गई है जिस पर ऐसी अपील दायर की गई थी या प्रतिनिधित्व किया गया था। **स्पष्टीकरण**

स्पष्टीकरण : इस धारा में "शिकायतों के निवारण के लिए सेवा नियम" अभिव्यक्ति का अर्थ इस अधिनियम के तहत के अलावा, सेवा मामलों के संबंध में किसी भी शिकायत के निवारण के संबंध में समय-समय पर लागू नियम, विनियम, आदेश या अन्य साधन या व्यवस्थाएँ हैं।"

37. उपरोक्त प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 4 का अवलोकन करने पर, यह ध्यान दिया जाता है कि उक्त प्रावधान ने एक पीड़ित पक्ष का एक विस्तृत स्वरूप बनाया है, जिसे अपील के माध्यम से माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत उठाने की अनुमति दी जा सकती है। संक्षेप में, धारा 4 न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को सीमित करती है और इसे केवल सरकारी सेवकों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने तक सीमित करती है, जब वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्रभावित होते हैं। इसलिए, निम्नलिखित चर्चा के लिए एक अग्रदूत के रूप में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए, पीड़ित को एक सरकारी सेवक के विस्तृत स्वरूप में फिट होना चाहिए। यदि वह एक सरकारी सेवक नहीं है, तो पीड़ित अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं कर सकता है।

38. अब, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन **सरकारी सेवक** शब्द के दायरे में आता है, हमें **1976 के अधिनियम** के परिभाषा खंड पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा।

39. **1976 के अधिनियम की धारा 2(सी)** सरकारी सेवक शब्द को परिभाषित करती है। यह प्रावधान उन व्यक्तियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है जिन्हें '**सरकारी सेवक**' माना जा सकता है, जिसमें शामिल हैं: (i) एक व्यक्ति जो एक सिविल सेवा का सदस्य है या रहा है या जो राजस्थान सरकार के अधीन एक सिविल पद धारण करता है या कर चुका है, जिसमें विदेशी सेवा में ऐसा कोई व्यक्ति या जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के निपटान में रखी गई हैं; (ii) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण की सेवा में कोई भी व्यक्ति जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से राज्य सरकार के निपटान में रखी गई हैं; (iii) अनुबंध पर सेवा में एक व्यक्ति या एक व्यक्ति जो कहीं और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और राजस्थान सरकार के तहत फिर से नियोजित है।

40. इस प्रकार, परिभाषा उन व्यक्तियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करती है जिन्हें एक सरकारी सेवक के दायरे में शामिल किया जा सकता है, विशेष रूप से यह प्रावधान

करते हुए कि यह केवल एक व्यक्ति हो सकता है जो एक सिविल सेवा का सदस्य है या रहा है या जो राजस्थान सरकार के अधीन एक सिविल पद धारण करता है या कर चुका है।

41. उपरोक्त चर्चा से, हमें अब **धारा 2(ए)** पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि '**सिविल सेवा**' शब्द का अर्थ सुनिश्चित किया जा सके और यह समझा जा सके कि ऐसे '**सिविल सेवा**' प्रदान करने वाले व्यक्ति को सरकारी सेवक माना जा सकता है।

42. तदनुसार, यह ध्यान दिया जाता है कि **धारा 2(ए)** '**सिविल सेवाओं**' को दो तरीकों से परिभाषित करती है:

(i) राज्य की सिविल सेवाएँ; और

(ii) ऐसी अन्य सेवाएँ जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

43. इसलिए, एक पीड़ित व्यक्ति के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने में सक्षम '**सरकारी सेवक**' के स्वरूप में फिट होने के लिए, ऐसे व्यक्ति को '**सिविल सेवा**' प्रदान करनी चाहिए। अनजाने में, एक व्यक्ति जो ऐसी '**सिविल सेवा**' प्रदान नहीं करता है, वह '**सरकारी सेवक**' नहीं होगा और तदनुसार, उसे अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने से रोक दिया जाएगा।

44. इस प्रकार, इस स्तर पर, इस न्यायालय को अब यह पता लगाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को **धारा 2(ए)**

की दोहरी परिभाषा के अनुसार 'सिविल सेवा' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं।

45. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि **सिविल सेवा** उन सरकारी अधिकारियों के निकाय को संदर्भित करती है जो सिविल व्यवसायों में कार्यरत हैं जो न तो राजनीतिक हैं और न ही न्यायिक। बल्कि, वे राज्य की '**कार्यपालिका**' हैं, जिन्हें समाज की R भलाई और राज्य के बेहतर प्रशासन के लिए, केवल सरकार के दायरे में कार्य करने और निर्वहन करने का कार्य सौंपा गया है।

46. इसलिए, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल, जो एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसे **कंपनी अधिनियम, 1956** के प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से निगमित किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार की बहुमत शेयरधारिता है, की सेवाओं को '**सिविल सेवा**' प्रदान करने के रूप में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल '**कार्यपालिका**' नहीं है। यह केवल एक कंपनी है जिसे 1956 के कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित किया गया है, जो कुछ कार्यों का निर्वहन करती है जो सरकार भी कर सकती है, लेकिन वह ऐसा न करने का विकल्प चुनती है। इसलिए, कुछ हद तक, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल जैसी कंपनियां जो सरकार के समान कार्यों का निर्वहन करती हैं, उन्हें केवल राजस्थान सरकार के **साधन** कहा जा सकता है, लेकिन स्वयं में **सरकार नहीं**। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल कार्यपालिका नहीं है।

47. इसके अलावा, कार्यपालिका जिसमें सरकारी सेवक होते हैं, को एक निगम के कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता है, जैसे कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल, जिसका मस्तिष्क और नियंत्रण पूरी तरह से उसके निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे निगम में 100% शेयरधारिता राज्य सरकार की है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी की पहचान स्वयं सरकार से अलग होती है।

48. तदनुसार, धारा 2(ए) के माध्यम से शामिल परिभाषा के अनुसार, केवल अन्य मार्ग जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों की सेवाओं को 'सिविल सेवा' के रूप में माना जा सकता है, वह राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में उक्त सेवाओं की मान्यता के माध्यम से है। आधिकारिक राजपत्र में ऐसी किसी भी मान्यता के अभाव में, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सिविल सेवा नहीं कहा जा सकता है।

49. आधिकारिक राजपत्र में उक्त मान्यता के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि तर्कों के दौरान, यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल की सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई थी। बल्कि, यहां तक कि विद्वान महाधिवक्ता ने भी आज तक आधिकारिक राजपत्र में पहले से ही दी गई उक्त मान्यता की पुष्टि नहीं की। इसलिए, यह एक तथ्य है कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल/निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को राजस्थान सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सिविल सेवाओं के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

50. इसलिए, संक्षेप में, यह ध्यान दिया जाता है कि 1976 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारी एक 'सरकारी सेवक' के स्वरूप में फिट नहीं होते हैं जो वैधानिक रूप से माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने में सक्षम है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी 1976 के अधिनियम की धारा 2(सी) द्वारा निर्धारित 'सरकारी सेवक' होने की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, क्योंकि ऐसे कर्मचारी कार्यपालिका का हिस्सा नहीं बनते हैं। बल्कि, वे केवल एक सार्वजनिक सूचीबद्ध निगम/कंपनी में कार्यरत हैं, जिसमें राजस्थान सरकार की बहुमत शेयरधारिता है। फिर भी, सरकारी कंपनी, यानी जेवीवीएनएल, स्वयं सरकार से अलग है, क्योंकि पूर्व का मस्तिष्क और नियंत्रण पूरी तरह से उसके निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में है, न कि सरकार के, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे निगम में 100% शेयरधारिता राज्य सरकार की है। इसके अलावा, यह एक तथ्य है कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को भी राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में 'सिविल सेवाओं' के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए, एक स्वाभाविक निहितार्थ के रूप में, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारी 1976 के अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं और परिणामस्वरूप, ऐसे कर्मचारियों को अपनी शिकायत के निवारण के लिए माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

51. इस समय, इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा करना विवेकपूर्ण होगा जैसा कि अनिल पारीक (उपरोक्त) में प्रतिपादित किया गया है, जहां न्यायालय के

समक्ष विवाद राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के संबंध में **1976 के अधिनियम** के प्रावधानों के तहत माननीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित था। खंडपीठ ने इस प्रकार माना:

“14. उपरोक्त परिभाषा खंड का सामान्य पठन **राजस्थान राज्य की सिविल सेवाओं** और ऐसी अन्य सेवाओं का अर्थ है जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। अपीलकर्ता का संबंध राजस्थान राज्य की सिविल सेवाओं से नहीं है, इसलिए, **राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन** के तहत सेवाओं को **1976 के अधिनियम की धारा 2(ए)** में परिभाषित '**सिविल सेवाओं**' की परिभाषा में शामिल करने का एकमात्र तरीका राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तहत सेवाओं को सिविल सेवाओं के रूप में अधिसूचित करना है। ऐसी किसी भी अधिसूचना के अभाव में, **राजस्थान राज्य फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन** के एक कर्मचारी को **1976 के अधिनियम की धारा 2(सी)** के तहत परिभाषित '**सरकारी सेवक**' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

15. अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तहत सेवाओं को सिविल सेवाओं के रूप में शामिल न करने का परिणाम यह है कि **1976 के अधिनियम** के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के एक कर्मचारी के किसी भी सेवा मामले से उत्पन्न होने वाली सेवाओं को प्रभावित करने वाली अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, हम यह मानते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सरकारी सेवक को वैधानिक अपील का उपाय अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है।

17. उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, माननीय एकल न्यायाधीश का यह आदेश कि अपीलकर्ता के पास राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौतीपूर्ण स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने के लिए एक

वैकल्पिक उपाय हैं, को अवैध घोषित किया जाता है और परिणामस्वरूप, 10.08.2023 के चुनौतीपूर्ण आदेश को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को उसके गुण-दोष पर विचार के लिए उसकी मूल संख्या पर बहाल किया जाता है।"

52. माननीय न्यायाधिकरण ने, 13.04.2022 के चुनौतीपूर्ण आदेश को पारित करते समय, कानून में यह मानने में त्रुटि की कि न्यायाधिकरण अनंत काल से चली आ रही पिछली/प्रथागत प्रथा के आधार पर याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने के लिए क्षेत्राधिकार में सक्षम होगा। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया तर्क निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है:

(i) कि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार एक कानून की देन है, यानी 1976 का अधिनियम।

(ii) कि यदि पीड़ित कर्मचारी 'सरकारी सेवक' के स्वरूप में फिट नहीं होता है जिसे उक्त अपील दायर करने की अनुमति है, तो ऐसे कर्मचारी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क करने से वैधानिक रूप से रोका जाएगा।

(iii) कि 1976 के अधिनियम की योजना के अनुसार और साथ ही, ऊपर दर्ज किए गए संबंधित अवलोकनों के अनुसार, यह स्थापित है कि याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं हैं और न ही उनकी सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सिविल सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई है।

(iv) कि माननीय न्यायाधिकरण और/या याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों को लड़ने की पिछली प्रथा को एक **बाध्यकारी मिसाल** के रूप में नहीं लिया जा सकता है, खासकर जब वैधानिक उल्लंघन के आधार पर अपील की स्वीकार्यता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई जाती है।

(v) एक **वैधानिक गलत**, भले ही वह बार-बार किया गया हो, को धार्मिकता धारण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और परिणामस्वरूप, एक अवैधता को स्थायी नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह एक अप्रासंगिक विचार होना चाहिए था कि क्या न्यायाधिकरण ने अतीत में जेवीवीएनएल द्वारा एक अपील को स्वीकार किया है या नहीं; और भी अधिक, जब न्यायाधिकरण को **अनिल पारीक (उपरोक्त)** में प्रतिपादित कानून की स्थापित स्थिति से अवगत कराया गया था।

53. इसी तरह, प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यापक कारण यह है कि एक **वैधानिक गलत**, भले ही वह बार-बार किया गया हो, को धार्मिकता धारण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और परिणामस्वरूप, एक अवैधता को स्थायी नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि न्यायाधिकरण ने पहले जेवीवीएनएल के खिलाफ अपीलों को स्वीकार किया था, अप्रासंगिक होगा, खासकर जब यह स्थापित हो गया है कि उक्त निगम के कर्मचारियों को **1976 के अधिनियम** की योजना के अनुसार न्यायाधिकरण से संपर्क करने से **वर्जित** किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल द्वारा राज्य-जैसे कार्यों को करने के संबंध में दिए गए तर्क के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि भले ही

जेवीवीएनएल ने राज्य के समान कार्यों का निर्वहन किया हो, फिर भी निगम को केवल राजस्थान सरकार का एक **साधन** कहा जा सकता है, लेकिन स्वयं में **सरकार नहीं**।

54. परिणामस्वरूप, उपरोक्त कारणों से, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने के लिए न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका के माध्यम से की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए।

55. समानांतर रूप से, यह ध्यान दिया जाता है कि तर्कों के दौरान, हाथ में विवाद के दूरगामी प्रभावों को देखते हुए, इस न्यायालय ने न्यायालय के रजिस्ट्रार को माननीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष जेवीवीएनएल, आरएफ सी, रीको सहित निगमों से संबंधित लंबित मामलों के आँकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे संभावित रूप से वर्तमान याचिका के परिणाम से सीधे प्रभावित हो सकते थे।

56. जवाब में, रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने **30.04.2024** के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि कुल मिलाकर, विभिन्न निगमों/कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा दायर **104 मामले** माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से 52 अपीलें जेवीवीएनएल/एवीवीएनएल के खिलाफ, 1 कृषि विपणन बोर्ड के खिलाफ, 1 कृषि उपज मंडी के खिलाफ और 52 विभिन्न नगरपालिकाओं के खिलाफ दायर की गई हैं। जबकि, इस न्यायालय के समक्ष, निगमों के खिलाफ निम्नलिखित संख्या में मामले लंबित होने की सूचना दी गई है:

1.	वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	26
2.	आर.एस.ई.बी	65
3.	जेवीवीएनएल	656

4.	एवीवीएनएल	208
5.	जेडीवीवीएनएल	1
6.	आरआरवीपीएनएल	244
7.	आरआरवीयूएनएल	118
8.	राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन	2
9.	रीको	29
10.	आरएफसी	32
11.	राज्य उद्यम (अन्य)	2
12.	आर.एस.आर.टी.सी	3161
13.	आर.एस.आर.डी.सी.	19
14.	आर.एच.बी.	109
15.	आर.एस.बी.सी.सी	2
16.	डेयरी फेडरेशन	100
17.	आर.एस.आर.डी.सी.	20
18.	यूनिवर्सिटी	746

निगमों के विरुद्ध लंबित सेवा मामला

57. इसके अलावा, 'सेवा रोस्टर' में बैठते हुए, इस न्यायालय ने समय-समय पर कई याचिकाएँ देखी हैं जहाँ निगमों के कर्मचारी, जिनमें राज्य सरकार एक बहुमत/एकमात्र शेयरधारक है, और जो राज्य के समान कार्यों का निर्वहन करते हैं, उन्होंने सीधे इस न्यायालय से संपर्क किया है, जिसमें तथ्य के विवादास्पद प्रश्न शामिल हैं, बिना पहले अपने नियोक्ताओं के समक्ष अभ्यावेदन के माध्यम से अपनी शिकायतें उठाए। ऐसे निगमों के कर्मचारियों द्वारा पहली बार में उच्च न्यायालय से संपर्क करने की यह प्रथा सीधे तौर

पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सिविल सेवाओं के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने का परिणाम है, जिससे ऐसे कर्मचारियों को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी अपील दायर करने से रोका जाता है, जो सेवा मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ निकाय है।

58. संक्षेप में, राज्य-जैसे कार्य प्रदान करने वाले निगमों के कर्मचारियों के लिए माननीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने के रास्ते में आने वाली बाधा उन सेवाओं की राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में गैर-मान्यता है, जिसे यदि अधिसूचित किया जाता है, तो अनजाने में ऐसे कर्मचारियों को एक वैकल्पिक उपाय का उपयोग करने और अपने शिकायतों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा, जो अक्सर उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य के विवादास्पद प्रश्नों के साथ दायर किए जाते हैं।

59. तदनुसार, यहाँ ऊपर सूचीबद्ध टिप्पणियों को करने के बाद, यह न्यायालय भारत के संविधान के **अनुच्छेद 226** के तहत पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता है और एक आँख बंद करने वाला दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है, जब यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित अपीलों का एक बड़ा हिस्सा ऊपर प्रतिपादित फैसले से सीधे प्रभावित होगा। इसलिए, यह न्यायालय निम्नलिखित सुझावों को आगे बढ़ाना उचित समझता है:

59.1 इस न्यायालय के **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1665/2024** जिसका शीर्षक *पवन मीना बनाम राजस्थान राज्य और अन्य* में पहले प्रतिपादित फैसले के आलोक में, निगमों और राज्य सरकार दोनों के पीड़ित कर्मचारी, अपनी शिकायत के

निवारण के लिए पहले उपाय के रूप में, एक अभ्यावेदन के माध्यम से अपने नियोक्ता से संपर्क करें। उक्त उपाय के लिए तर्क इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि नियोक्ता के अलावा कोई भी प्राधिकरण कर्मचारियों की शिकायत और विवाद के तथ्यों की बारीकियों से अधिक परिचित नहीं होगा। हालांकि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अभ्यावेदन को प्रतिकूल रूप से तय किया जाता है, तो कर्मचारी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए सक्षम मंच से संपर्क करने का हर अधिकार होगा।

59.2 राजस्थान सरकार, इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य-जैसे कार्य प्रदान करने वाले निगमों के कर्मचारियों के लिए माननीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने के रास्ते में आने वाली एकमात्र बाधा उन सेवाओं की राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में गैर-मान्यता है, इन निगमों के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवाओं को सिविल सेवाओं के रूप में अधिसूचित करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है, जो अनजाने में ऐसे कर्मचारियों को **1976 के अधिनियम की धारा 2(सी)** के तहत परिभाषित **सरकारी सेवक** के रूप में योग्य बनाएगा, जो न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत उठा सकेंगे।

59.3 आधिकारिक राजपत्र में निगम के कर्मचारियों की ऐसी अधिसूचना के अभाव में, कर्मचारी कानून के समक्ष किसी भी वैकल्पिक और प्रभावी उपाय से वंचित हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे तथ्य के विवादास्पद प्रश्नों के साथ पहली बार में ही उच्च न्यायालय से संपर्क करते हैं। बल्कि, यदि उनकी सेवाओं को अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, कर्मचारियों को एक वैकल्पिक उपाय से सुसज्जित किया जाएगा, जो विशेष

रूप से 'सेवा' मामलों पर न्यायनिर्णयन करने के लिए डिज़ाइन किए गए मंच के समक्ष होगा, जिसमें प्रशासनिक कानून के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

60. तदनुसार, राज्य सरकार, विद्वान महाधिवक्ता, प्रधान सचिव (कानून) और मुख्य सचिव को उपरोक्त निर्देशों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और यदि उचित समझा जाए, तो आधिकारिक राजपत्र या अन्यथा में अधिसूचनाओं के माध्यम से ऐसे आवश्यक परिवर्तन करने का निर्देश दिया जाता है, जो ऐसे निगमों के कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक मंच के समक्ष शिकायतें उठाने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, जो राज्य सरकार के समान कार्यों का निर्वहन करते हैं।

अंतिम टिप्पणियाँ

61. अंत में, गुण-दोष के आधार पर, उपरोक्त अवलोकनों के संचयी दृष्टिकोण में, यह माना जाता है कि अधिसूचना के माध्यम से याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल की सेवाओं को 'सिविल सेवाओं' के रूप में शामिल न करने का परिणाम यह है कि **1976 के अधिनियम** के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल के एक कर्मचारी के किसी भी सेवा मामले से उत्पन्न होने वाली सेवाओं को प्रभावित करने वाली अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

62. परिणामस्वरूप, गुण-दोष के आधार पर, वर्तमान याचिका को की गई प्रार्थनाओं के अनुसार **अनुमति** दी जाती है।

63. इसके अतिरिक्त, **20.09.2021** के आदेश को भी **रद्द और समाप्त** किया जाता है, इस शर्त के साथ कि आगे चलकर, याचिकाकर्ता-जेवीवीएनएल, यदि कोई प्रशासनिक

आवश्यकताएं हों, तो उनका विधिवत ध्यान रखने के बाद, इस आदेश के पारित होने की तारीख से **पंद्रह दिन की अवधि** के भीतर प्रतिवादियों के संबंध में आगे के स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

64. इस निर्णय की एक प्रति रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (कानून), महाधिवक्ता और अन्य संबंधित विभागों को उनके उचित अवलोकन/विचार और अनुपालन के लिए भेजी जाए।

(समीर जैन),जे

जेकेपी/9-12

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate